



THE CONTRIBUTION OF SKILL DEVELOPMENT IN RURAL YOUTH DEVELOPMENT

ग्रामीण युवाओं के विकास में कौशल विकास का योगदान

Mohd Faisal Isa

Junior Research Fellow, Education Department, University of Allahabad, India.

ABSTRACT

“भारत का भविष्य गाँवों में बसता है”-महात्मा गांधी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 68 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। वर्तमान समय के आँकड़े बताते हैं कि भारत की कामकाजी जनसंख्या 2040 तक चीन की कामकाजी जनसंख्या को पछाड़ देगी। कौशल विकास पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपने 15 वर्षों से अधिक के अनुभवों से अर्जित ज्ञान द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के रूप में 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित किया है। अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद कौशल भारत कुशल भारत के घोष वाक्य के साथ शुरू कौशल विकास मिशन कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

कुंजी शब्द— ग्रामीण, जनसंख्या, कौशल विकास

प्रस्तावना:

“भारत का भविष्य गाँवों में बसता है”-महात्मा गांधी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 68 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारत में 6.4 लाख गाँव हैं और भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र है, फिर भी यह अनुमान है कि 2050 तक आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करेगी। यदि देश की ग्रामीण-शहरी संरचना पर गौर करें तो भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक-आर्थिक उन्नति के नए आयामों तक पहुँचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे अहम भूमिका होगी, क्योंकि आगामी कुछ दशकों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा, जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़नी है। कुल ग्रामीण आबादी में जहाँ 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया था कि भारत युवाओं का देश है। वाकई मैं युवाओं की जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, 15-24 वर्ष तक के नौजवानों को युवा कहा जाता है। यह वह समय है जब बच्चे अनिवार्य शिक्षा पूरी कर पहली बार रोजगार की तलाश में निकलते हैं, किन्तु भारत की राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 15-29 वर्ष तक नौजवानों को युवा माना गया है और हमारी जनसंख्या में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 27.5 प्रतिशत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में युवा की परिभाषा ऐसे युवाओं के रूप में की है जो 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जबकि श्रम ब्यूरो ने 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वालों को युवा की श्रेणी में रखा है।

जनांकिकीय लाभांश की दृष्टि से भारत को अपने कार्यबल को कौशलपूर्ण करना न सिर्फ अपने लिए अपितु दुनिया की संभावनाओं से लाभान्वित होने के लिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वर्ष 2025 तक भारत की आबादी 1.4 अरब तक पहुँचने के आसार हैं। भारत की जनसंख्या जैसे-जैसे युवा होगी, स्थायी रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण होता जाएगा। भारत के सामने अभी जो महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, वह यह है कि देश के सबसे उत्पादक समूह (15 से 60 वर्ष के बीच उम्र वाली जनसंख्या) का विस्तार होगा। हमारी कार्यशील आबादी वर्ष 2011 के 76.1 करोड़ के मुकाबले बढ़कर वर्ष 2020 में 86.9 हो जाएगी और इस अवधि में कार्यशील आबादी की वृद्धि दर कुल आबादी की वृद्धि दर से अधिक होगी।

वर्तमान समय के आँकड़े बताते हैं कि भारत की कामकाजी जनसंख्या 2040 तक चीन की कामकाजी जनसंख्या को पछाड़ देगी। स्पष्ट है कि हमारे देश की ‘कुल कार्य योग्य जनसंख्या’ अर्थात् किसी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों की संख्या के मामले में बढ़त प्राप्त है, किन्तु उज्ज्वल भविष्य के लिए केवल कार्य योग्य जनसंख्या में वृद्धि पर ही विश्वास नहीं कर सकते। देश के लगभग 50 करोड़ के कार्यबल में सिर्फ 14 प्रतिशत को औपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त है और 86 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में नियुक्त हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास योजना:

गाँवों की विविधता और बहुमुखी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कौशल विकास के लिए राष्ट्रव्यापी, क्षेत्र आधारित और

समुदाय केन्द्रित योजनाओं का संचालन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपने 15 वर्षों से अधिक के अनुभवों से अर्जित ज्ञान द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम को **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई)** के रूप में 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित किया है। यह राष्ट्रव्यापी रोजगार से जुड़ा मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका वित्त पोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाना है। इसमें 18 से 35 आयु के ग्रामीण युवकों के लिए पीपीपी मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़े 3, 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसमें एससी/एसटी को 50 प्रतिशत, महिलाओं को 33 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत अनिवार्य कवरेज दिया गया है। इसमें प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत को रोजगार दिलाए। इसके तहत वर्ष 2016-17 में 1.49 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 74 हजार अभ्यर्थियों को 329 व्यवसायों में रोजगार दिया गया है। इस योजना के दिशानिर्देश, मार्गदर्शी सिद्धान्त और सुविधा शर्तें इसकी वेबसाइट (<http://ddugky.gov.in>) पर उपलब्ध हैं। यह योजना अभी 24 राज्यों के 617 जिलों में लागू है जिसमें 281 से अधिक पीआईए भागीदार हैं और इसमें 39 क्षेत्रों के 329 से अधिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य:

देश के अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार परक बनाना। विकास के नये क्षेत्र उत्पन्न करना। कौशल विकास के अन्य उद्देश्य निम्न हैं—

- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये हैं, उनके अन्दर के कौशलों की पहचान करना।
- ज्यादा से ज्यादा युवाओं के अन्दर के कौशलों को पहचान कर उन्हें उनकी रुचि, क्षमता तथा योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार योग्य बनाने और उनकी जीविका निश्चित करने में सक्षम बनाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
- देश के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को रोजगार परक बनाकर देश के विकास में सम्मिलित करना।

कौशल विकास योजना की चुनौतियाँ:

कौशल विकास वर्तमान समय में भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में अगले दशक में 15-59 की आयु समूह के लोगों की प्रधानता होगी। 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी। इसकी तुलना में अमेरिका में यह 40 वर्ष, यूरोप में 46 वर्ष, और जापान में 47 वर्ष होगी। भारत की युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। परन्तु भारत की प्रशिक्षण क्षमता सीमित है। सही संख्या के बारे में हालांकि कोई मत एक नहीं है, फिर भी अनुमान है कि हर वर्ष करीब 50 लाख युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसलिए भारत के कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष निम्न चुनौतियाँ भी हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

- भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण वातावरण की रीढ़ समझे जाने वाले भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की वर्तमान वार्षिक क्षमता केवल 25 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने की है। इसलिए, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता और आकार बढ़ाना भारत के लिए एक तात्कालिक नीति प्राथमिकता है।
- युवाओं में यह कोई प्रेरक करियर नहीं बन पा रहा है। इसे मेन स्ट्रीम करियर विकल्प समझने की बजाए दोयम दर्जे का विकल्प समझा जाता है।
- नियोक्ताओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी कर्मिकों की तुलना में भर्ती के स्तर पर इंजीनियरों को उच्चतर वेतन प्रदान करना।
- औपचारिक शिक्षा वर्तमान समय में भी युवाओं के लिए शीर्ष पसन्द बनना।

कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के प्रयास:

अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय कौशल विकास नीति' जारी की थी। इसके अनुसार 10000 करोड़ रुपये से वर्ष 2022 तक 50 करोड़ उच्च-स्तर के कुशल व्यक्तियों को तथा 'राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद' के जरिए बड़ी संख्या में गुणवत्तापरक संस्थाओं का सृजन करके उनके जरिए 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके कुशल कामगार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शेष 35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार के 18 विभागों द्वारा उपाय शुरू किए जाने थे। वर्तमान समय में देश की युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' की शुरुआत तथा 'नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2015 को की, साथ ही 'कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का प्रोन्नयन 'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएस)' के रूप में किया गया जो देशभर में विभिन्न योजनाओं और संगठनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। देशभर के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता नेटवर्क द्वारा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से कौशल विकास पहल योजना (एसडीआईएस) शुरू की गई है जिसके तहत 70 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु 629 मॉडल तैयार किए गए हैं। इनमें से 129 मॉडल राष्ट्रीय कौशल ढांचा अर्हता के अनुरूप हैं।

कौशल विकास पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय भारत सरकार के 20 मंत्रालय और विभाग देश में 47 कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाएं चला रहे हैं तथा 22 मंत्रालय और विभागों ने वर्ष 2016-17 में 99.35 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक 19.58 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। मंत्रालय प्रशिक्षार्थियों को सीएनसी मशीनिंग, आटोमोटिव तकनीक, वेल्डिंग, प्लंबिंग, निर्माण जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कौशल निखारने हेतु देशभर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित कर रहा है और ऐसा पहला संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल कौशल विकास निगम (एनएसडीसी):

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित यह एक गैर लाभ अर्जक कंपनी है। यह देश में कौशल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है। अब यह एमएसडीसी का हिस्सा है और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाना है। यह कौशल विकास के विस्तार हेतु देशभर में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना कर रहा है। अब तक 36 एसएससी स्थापित द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता क्षेत्रों तथा मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करती है। इसके अलावा एनएसडीसी ने इनकी मदद से प्रशिक्षण संचालन के लिए 34 क्षेत्रों के 348 मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इसके अलावा एनएसडीसी गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित जम्मू-कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए 'उड़ान' योजना चला रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में राज्य के 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करना है जिसके तहत अब तक 25 हजार युवाओं को कवर किया गया है जिसमें 17 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:

देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है, इसके द्वारा कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिकों की अकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुमुखी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत 20 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हैं जिन्होंने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के कौशललीकरण लक्ष्य क्रमशः 125.69 और 117.50 लाख की तुलना में क्रमशः 104.16 और 60.32 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन (पीएमकेवीवाई):

यह एमएसडीसी की परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण की योजना है। इस कौशल

प्रमाणन व पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम-आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने, नियोजनीय बनने, अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाना और प्रेरित करना है। इस योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 2017 तक 31.22 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें करीब 17 लाख पुरुष और 14 लाख महिलाएं हैं। इस योजना के जरिए कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी के माध्यम से सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के प्रत्येक जिले में मॉडल कौशल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र योजना चल रही है। जिसके तहत 16 जुलाई, 2017 तक देश के 514 जिलों में 556 पीएमकेवीवाई के आवंटित किए गए हैं जिनमें से 212 खोले जा चुके हैं। पीएमकेवीवाई का पूरा फोकस रोजगार पर है और इसमें 50 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को मजदूरी युक्त रोजगार में तैनात करना आवश्यक है। अब तक 2.9 लाख अभ्यर्थियों को तैनाती का ऑफर प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त सरकारी प्रयासों के बावजूद कौशल भारत कुशल भारत के घोष वाक्य के साथ शुरू कौशल विकास मिशन कम चुनौतिपूर्ण नहीं है, क्योंकि कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में प्रसार हेतु जनांकिकीय लाभांश प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें हैं और आज देश श्रमाधिक्य के दौर से गुजर रहा है जहां ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक एवं युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में यदि पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ बेरोजगारी के शिकार अकुशल श्रमिकों एवं युवाओं को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रमिक बना भी दिया जाता है उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि निकट भविष्य में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। तमाम चुनौतियों, आशांकाओं के बावजूद आशाजनक पहलू यह है कि वर्तमान में भारत को प्राप्त जनांकिकीय लाभांश की स्थिति अगले 30 वर्षों तक रहने वाली है। यदि देश का नेतृत्व इस स्थिति का उपयोग करने में सफल हो पाता है तो देश के समक्ष विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनने का अपार संभावनाएं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. गजेन्द्र, एस. (2017), ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास: आवश्यकता और प्रयास, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका (अंक 11), सितम्बर 2017, पृष्ठ 26-31।
2. मेहरा, एस. सी. (2017), स्किल इंडिया: आर्थिक विकास के लिए अनिवार्यताएं, भूगोल और आप द्विमासिक पत्रिका (अंक 95), नवम्बर-दिसम्बर 2017, पृष्ठ 6-7।
3. मिश्रा, आर. (2002), विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिरुचि एवं उपलब्धि का अध्ययन, डाक्टोरल डिजिटेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. सिंह, एस. (2016), कौशल विकास, दिल्ली: अग्नि प्रकाशन।
5. शर्मा, एच. (2017), कौशल विकास को रोजगार से जोड़ना जरूरी, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका (अंक 11), सितम्बर 2017, पृष्ठ 22-24।